बिहार विधान परिषद्

186वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 05

शुक्रवार, तिथि — 03 भाद्र, 1939 (श.) / 25 अगस्त, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 13

1.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	-	-	02
2.	शिक्षा विभाग	-	-	10
3.	खान एवं भूतत्व विभाग	-	-	01
			कुल योग –	13

बाल उद्यान का विकास

33. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी शहर में गायत्री मंदिर के पीछे भारत के दो बार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाले महामहिम डा. राजेन्द्र प्रसाद बाल उद्यान में राष्ट्रपति जी की मूर्ति लगी है परंतु देखभाल न होने की स्थिति में जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल की देखरेख डा. राजेन्द्र प्रसाद सेवा संस्थान, मोतिहारी के द्वारा की जाती है परन्तु आ्रर्थक परेशानियों के कारण रख-रखाव सही नहीं हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में बापू के स्थलों का विकास कर रही है, वहीं डा. राजेन्द्र प्रसाद बाल उद्यान, मोतिहारी का विकास करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

महाविद्यालयों की संबद्धता

34. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय ने 58 अनुदानित डिग्री कॉलेजों की संबद्धता रद्द कर दी है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में जनसंख्या के आधार पर जितने डिग्री कॉलेज होने चाहिए उतने डिग्री कॉलेज नहीं हैं, उसके बावजूद भी संबद्धता को रद्द करना छात्रों एवं शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है;

(ग) क्या यह सही है कि जिन डिग्री कॉलेजों की संबद्धता रद्द की गई है, उन कॉलेजों की संपत्ति करीब 10 से 15 करोड़ के बीच है, उन कॉलेजों एवं शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों का सरकार क्या करेगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन महाविद्यालयों को संबद्धता देने का विचार रखती है ताकि गरीब छात्रों एवं कर्मियों को दर-दर की ठोकर न खाना पड़े?

अवैध खनन पर कार्रवाई

35. **श्री केदारनाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी के निकट बिहटा, मनेर, कोइलवर आदि क्षेत्रों में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अधिकतर बालू घाटों की नियमानुकूल बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व भी ठप्प है;

(ग) क्या यह सही है कि बिना टेंडर एवं बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण बालू की अवैध खुदाई की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूरे राज्य में विशेषकर पटना जिले में बालू का अवैध खनन रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई

36. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा कार्यालय, बक्सर में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त हिमाद्री कुमार लिपिक की नियुक्ति अनुकंपा पर अवैध रहने के कारण जिला पदाधिकारी, बक्सर से जांच की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि हिमाद्री कुमार, लिपिक के वर्ष 1996 से 2017 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, बक्सर में पदस्थापित रहते हुए उन पर गंभीर आरोप लगे और वे जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा के कार्यालय में स्थानान्तरण आदेश एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना के ज्ञापांक-169, दिनांक 18.2.2017 के आदेश का अनुपालन न कर वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर बक्सर में ही पदस्थापित/प्रतिनियुक्त हैं;

(ग) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना के ज्ञापांक-4, दिनांक 3.1.2011 के द्वारा हिमाद्री कुमार, लिपिक पर प्रपत्र 'क' गठन कर विभागीय कार्यवाही के आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना के ज्ञापांक-4, दिनांक 3.1.2011 एवं ज्ञापांक-169, दिनांक 18.2.2017 का अनुपालन कराते हुए हिमाद्री कुमार, लिपिक एवं बचाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों के अनुदान का भुगतान

37. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के भुगतान हेतु अनुदान की राशि (वर्ष 2017) जिलों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के कार्यालय में आ चुकी है;

(ख) क्या यह सही है कि ऑनलाइन प्रक्रिया बन्द रहने के कारण शिक्षकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कराकर शीघ्र इन शिक्षकों के अनुदान का भुगतान कराना चाहती है?

पदस्थापन कबतक

38. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला में कतिपय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी नियमों एवं परंपराओं के अनुसार प्रत्येक तीन वर्षों के बाद अधिकारियों के स्थानान्तरण की व्यवस्था है;

(ग) क्या यह सही है कि इन पदाधिकारियों के इतने लम्बे अर्से से एक ही जगह पदस्थापित रहने से स्थानीय लोगों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लम्बी अवधि से पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उस जिला के बाहर के जिला में पदस्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

जिम चालू कबतक

39. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित पटना कॉलेज कैम्पस में विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने हेतु 1950 के दशक में जिमनैजियम की स्थापना की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि विगत दो दशक से यह जिमनैजियम बंद है तथा भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिमनैजियम भवन का जीर्णोद्धार कराते हुए जिम चालू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अनुदान एवं सेवाशर्त्त

40. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्तरहित माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों एवं डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों को वित्तसहित शिक्षा नीति, 2008 के आलोक में परीक्षाफल के आधार पर अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि यह अनुदान इन शिक्षण संस्थानों को तीन-तीन स्रोतों से जांचोपरान्त दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 तक का अनुदान भी आधा-अधूरा भुगतान किया जा सका है, यानी वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 पांच शैक्षणिक सत्रों का अनुदान नहीं दिया गया है जिससे शिक्षक और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं;

(घ) क्या यह सही है कि बजट सत्र में सरकार ने सदन को आश्वस्त किया था कि वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 का अनुदान मई, 2017 तक साथ ही 2014, 2015 एवं 2016 का अनुदान इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भुगतान कर दिया जायेगा एवं सेवाशर्त्त नियमावली एक महीना में अधिसूचित कर दी जायेगी;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के बकाये पांच वर्ष के अनुदान को एकमुश्त कबतक देना चाहती है, साथ ही सेवाशर्त्त नियमावली कबतक अधिसूचित करना चाहती है?

एन.सी.सी. कैडेट को बोनस अंक

41. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार एन.सी.सी. को तो बढ़ावा दे रही है परंतु एन.सी.सी. पूर्ण करने के बाद छात्र के भविष्य की कोई योजना नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ विकट परिस्थिति में भी एन.सी.सी. कैंप अटेंड करता है, कई बार तो उसे परीक्षा से भी वंचित रहना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को होने वाले परेड में राज्य के एन.सी.सी. कैडेट कड़ी मेहनत करके अपनी भागीदारी निभाते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि राज्य का नाम रौशन करने वाले एन.सी.सी. कैडेट को राज्य सरकार से कोई प्रमाण-पत्र तक नहीं मिलता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में एन.सी.सी. कैडेट को विशेष छूट तथा बोनस अंक देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सेवाशर्त्त नियमावली अधिसूचित नहीं

42. **श्री केदारनाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार स्थापना की अनुमति प्राप्त लगभग 700 उच्च विद्यालयों और लगभग 500 इंटर कॉलेजों और 250 महाविद्यालयों को छात्रों की उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान देती है;

(ख) क्या यह सही है कि इन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अभी तक कोई सेवाशर्त्त नियमावली अधिसूचित नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि अनुदान प्राप्त इन संस्थानों के पास लाखों-करोड़ों की चल-अचल संपत्ति है लेकिन सरकार उनका नियमन/नियंत्रण नहीं करना चाहती है जिससे उनकी उक्त संपत्ति का विचलन, गबन हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमे और निगरानी जांच के कारण शिक्षण प्रभावित हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 2017 तक बकाये अनुदान का भुगतान करते हुए इन संस्थानों की चल-अचल संपत्ति का नियमन और नियंत्रण तथा इन शिक्षकों की सेवाशर्त्त नियमावली अधिसूचित करना चाहती है ताकि गुणात्मक शिक्षा में इनका भरपूर योगदान हो सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालय का निर्माण

43. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के वार्ड नं.-22 नगर परिषद्, औरंगाबाद के कुशवाहा नगर में अभी तक बच्चों को पढ़ने हेतु प्राथमिक विद्यालय नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल के बच्चे लगभग 2 से 2.5 कि.मी. की दूरी तय कर विद्यालय जाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव में विद्यालय निर्माण हेतु आम गैर मजरूआ जमीन उपलब्ध है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त स्थल पर बच्चों को पठन-पाठन हेतु आम गैर मजरूआ जमीन पर विद्यालय का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

शिक्षकों की नियुक्ति

44. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सहित अन्य विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण उन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा नियुक्ति कार्यक्रम बढ़ाने से खंड 'क' में वर्णित विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बाधित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतायेगी कि किन कारणों से गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा अन्य विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति बाधित है और इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं और कबतक इन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति करने का सरकार विचार रखती है?

भवन का निर्माण

45. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत +2 एल.एम. उच्च विद्यालय, पुपरी की स्थापना आजादी से पूर्व 1932 में हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि अनुमंडल के प्रतिष्ठित इस विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या दो हजार से ज्यादा है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय का भवन जर्जर हो जाने के कारण समीप के मध्य विद्यालय के दो कमरों में पठन-पाठन की खानापूरी की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालयों के भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कबतक करना चाहती है?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 25 अगस्त, 2017